उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में केन्द्रीय सरकार की लगी पूंजी का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	करोड़ रुपये
1985–86 . .	777.59
1986–87 . .	603.60

1987–88 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के परीक्षित लेखे केवल सितम्बर, 1988 के अन्त तक ही उपलब्ध होते हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

घटिया कोयले का आयात

3359. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अच्छी क्वालिटी के कोयले के साथ घटिया स्तर के कोयले का, जो देश में उपलब्ध है, आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई विभिन्न क्वालिटी के कोयले की वर्षवार मात्रा कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने आयातित कोयले की क्वालिटी की जांच करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) "खुली लाइसेंस प्रणाली" के अधीन वास्तविक औद्योगिक प्रयोगकर्ता कच्चे माल के रूप मे प्रयोग के लिए कोयले का आयात कर सकते है । उच्च राख के अंश वाले देशी कोककर कोयले में मिश्रण हेतु तथा देशी स्रोतों से रह गई कमी पूरी करने की दृष्टि से इस्पात उद्योग कम राख के अंश वाला कोककर कोयले का आयात कर रहा है । ऐसा समझा जाता है कि मुख्य रूप से दक्षिणी क्षेत्र के सीमेंट उद्योगों द्वारा थोड़ी मात्रा में अकोककर कोयला आयात किया जाता है । आयातित कोयले की किस्म आम तौर पर बेहतर होती है अथवा देश में उत्पादित उच्च श्रेणी के कोयले से अच्छी होती है ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात क्षेत्र द्वारा आयातित किए गए कोककर कोयले को नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	कुल मात्रा (मिलियन टन में)
1985–86 . .	2.45
1986–87 . .	2.43
1987–88 . .	3.08

सीमेंट उद्योग विकास आयुक्त के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सीमेंट उद्योग द्वारा आयातित किए गए अकोककर कोयले की कुल मात्रा नीचे दी गई है :—

	लाख टन
1986–87 . .	0 86
1987–88 . .	1.31

इसके अलावा तमिलनाडु विद्युत बोर्ड ने भी 1985–86 के दौरान 92,738 टन कोयले का आयात किया ।

कम राख के अंश वाले कोककर कोयले के आयात को गुणवत्ता तथा देश में उसकी

उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जारी रखना पड़ा, किन्तु जुलाई, 1988 से रेल-सह-समुद्री-मार्ग के जरिए नियमित संयोजन की मंजूरी के अन्तर्गत पूर्वी क्षेत्र से दक्षिण को कोयला की ढुलाई करके दक्षिण के सीमेंट उद्योग की कुछ जरूरतों को पूरा किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं । पिछले कुछ महीनों के दौरान ई. सी. एल., बी. सी. सी. एल. तथा एन. ई. सी. के सभी रेल मार्ग से दक्षिण के उद्योग को कुछ मात्रा में कोयले की ढुलाई की गई है। तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के लिए ई. सी. एल. तथा बी. सी. सी. एल. जैसे संयोजन में भी वृद्धि की गई है ।

भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड का कार्य निष्पादन

3360. **श्री राम जैठमलानी :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यस सच है कि भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड को अब तक लाखों रुपये की हानि हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कम्पनी में अब तक कुल कितना निवेश किया जा चुका है और इस राशि के अतिरिक्त किन अन्य स्रोतों से निवेश किया गया और उस निवेश की राशि कितनी है ; और

(ग) मार्च, 1988 तक इस कम्पनी को कुल कितनी हानि हो चुकी है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय कम्पनी की चुकता पूंजी 1935 लाख रुपये है, जिसका सरकार ने सम्पूर्णरूप से अंशदान किया है।

(ग) 31-3-1988 तक संचित हानि 2737 लाख रुपये की है । हानियां मुख्यरूप से उच्च ब्याज दायित्व, लाभाकारी क्रयादेशों की कमी, कठोर प्रतियोगिता के कारण मामूली लाभ, वस्तु सूची के उच्च स्तर तथा विविध देनदारों के कारण हुई है । लागत मे कमी करने, उच्च तकनीकी क्षेत्रों में विविधीकरण करने एवं वस्तुसूची और विविध देनदारों को कम करने के लिए कदम उठाये गये हैं कार्य में सुधार लाने तथा निकटता से मानीटर करने के लिए कम्पनी को भारत यंत्र निगम नामक एक धारक कम्पनी के अधीन लाया गया है।

बकाया राशि का भुगतान करने में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को सहायता

3361. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से अपनी बकाया राशि का भुगतान तत्काल करने का आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए इस राशि की अदायगी करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ; और

(ग) यदि हां, तो कुल देय राशि कितनी है और क्या सरकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को राज्य सहायता देकर इस रकम का भुगतान करने में उसकी सहायता करेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकाया देय राशियों के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने अपनी वित्तीय बाधाओं का जिक्र किया है । 31 जुलाई, 1988 की स्थिति के अनुसार